



विकासखण्ड सरसावां (जनपद-सहारनपुर) में साक्षरता एवं शिक्षण संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन

मनजीत सिंह

शोध छात्र, भूगोल विभाग, भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।

डॉ. प्रेम शंकर पाण्डेय

असि0 प्रोफेसर, शोध पर्यवेक्षक भूगोल विभाग, भारतीय महाविद्यालय, फर्रुखाबाद

Article Info

Accepted : 05 Dec 2024

Published : 25 Dec 2024

Publication Issue :

November-December -2024

Volume 7, Issue 6

Page Number : 75-82

शोध सारांश — मानवीय संसाधनों के गुणात्मक पहलू को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा का अद्वितीय योगदान है, इसलिए शिक्षा सामाजिक-आर्थिक विकास का एक अनिवार्य अंग बन चुकी है। आधुनिकीकरण एवं सामाजिक जागरूकता के स्तर को साक्षरता प्रमुख रूप से प्रभावित करती है। किसी क्षेत्र के सम्पूर्ण सामाजिक व्यक्तित्व के ज्ञान के लिए साक्षरता का अध्ययन आवश्यक है। वस्तुतः शिक्षा को एक दिशा प्रदान करने एवं उनके प्रत्येक पहलुओं जैसे— सामाजिक कुरीतियों, भाषा संकीर्णता एवं जाति प्रथा आदि को परिमार्जित करने में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए संसाधनों के नवीनीकरण एवं प्रतिनिधि परिवर्तनों की दिशा में इसकी उपयोगिता विवाद रहित है, क्योंकि विकास की आत्मा के रूप में यह समाज का मूल आधार एवं वास्तविक मापदण्ड है। विकासखण्ड में शिक्षा मानव विकास का निर्धारण करता है, तथा उससे सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति निर्धारित होती है। शिक्षा का स्तर, व्यवसाय एवं आय तीनों एक साथ मिलकर समाज की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं इसलिए क्षेत्रीय विकास तथा सामाजिक परिस्थिति को ऊँचा करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं का उचित वितरण अपेक्षित है।

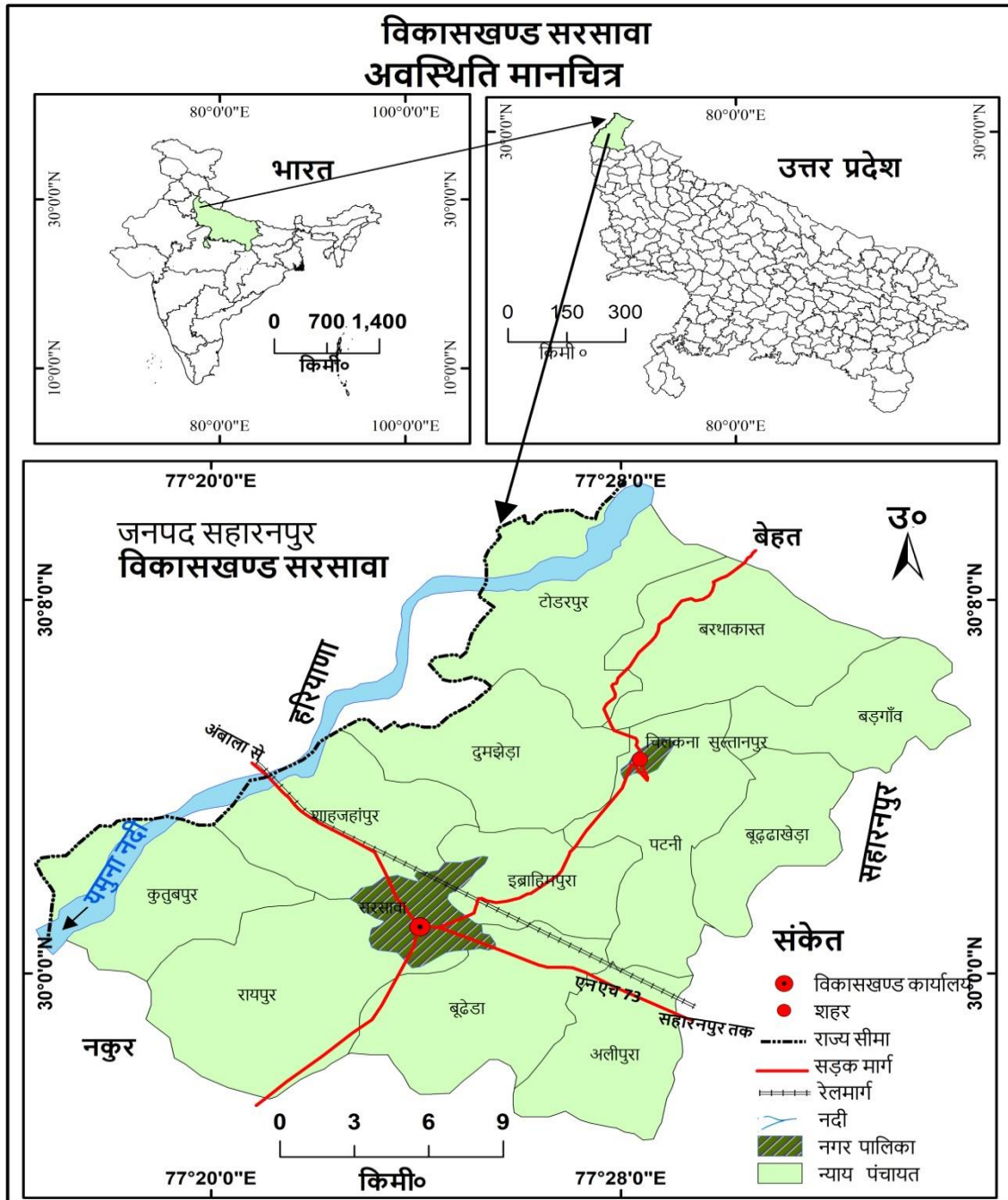
संकेत शब्द :- उद्यमशीलता विकास, सशक्तिकरण, बौद्धिक विकास, आधुनिकीकरण, साक्षरता ।

परिचय :- मानव का भौतिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास शिक्षा से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक नवीन

आर्थिक क्रियाओं में आधुनिक विधियों तथा तकनीकों का प्रयोग शिक्षा के माध्यम से ही सम्भव है (थपलियाल एवं रमन्ना, 1977)। शिक्षा के माध्यम से ही जनसंख्या अपने बुद्धि, कौशल एवं तकनीकी ज्ञान द्वारा नवीन खोजों से विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विकास में योगदान करने का प्रयास करती है। अतः साक्षरता किसी भी क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास तथा सामाजिक उत्थान का सूचक है (ओझा, 1984)। इसके अतिरिक्त शिक्षा आत्मविश्वास उत्पन्न करने, योजनाओं में भाग लेकर उनको मूर्तरूप प्रदान करने, क्षमता बढ़ाने, स्थानीय एवं राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण, राजनीतिक-सामाजिक चेतना, स्थानीय व राजनैतिक ढाँचे के परिवर्तन में अस्थायित्व को कम करने तथा आर्थिक समानता के लिए आवश्यक है (पाठक, 1993)। इन्हीं तत्त्वों को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधानों को मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में सम्मिलित किया है। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्त्वों की धारा 45 के अनुसार 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी; जबकि अनुच्छेद 21क में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है किंतु स्वतंत्रता के 60 वर्षों बाद भी इस कार्य में सफलता नहीं मिल पायी है। इस संदर्भ में गुन्नार मिर्डल का कथन समीचीन मालूम पड़ता है कि जनसंख्या के बहुत बड़े भाग को निरक्षर छोड़कर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम शुरू करने की बात निरर्थक प्रतीत होती है। इस आधारभूत सत्य को स्वीकार करके आठवीं पंचवर्षीय योजना में "सबको शिक्षा सबको काम" के लक्ष्य को केन्द्रीय महत्व प्रदान किया गया है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना में सर्व-शिक्षा अभियान को सम्मिलित किया गया है। अतः समन्वित विकास की दृष्टि से शैक्षिक सेवाओं एवं सुविधाओं का विकास अत्यन्त आवश्यक एवं उपयोगी हो जाता है।

अध्ययन क्षेत्र :-सहारनपुर जनपद के विकासखण्ड सरसावां का अक्षांशीय विस्तार 26023" उत्तर से 27030" उत्तर हैं तथा देशान्तरीय विस्तार 82016" पूर्व से 83020" पूर्व हैं एवं इसका क्षेत्रफल 179.93 वर्ग किमी. है। विकासखण्ड की सम्पूर्ण जनसंख्या 180176 (जनगणना 2011) है। विकासखण्ड मुख्यालय से निकटतम प्रमुख नगर गोरखपुर 52 किलोमीटर पूर्व में तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ 195 किलोमीटर पश्चिम में स्थित हैं। भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरयूपार मैदान के मध्य भाग में स्थित बस्ती जनपद के संरचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन क्षेत्र जलोढ़ पूरित गर्त का भाग है। इसमें जलोढ़ का जमाव हिमालय पर्वत की निर्माण प्रक्रिया से संबन्धित है; जो प्लीस्टोसीन काल से प्रारम्भ होकर अभी तक चल रही है। इस समतल मैदानी भू-भाग का निर्माण घाघरा एवं राप्ती नदियों द्वारा

लाए गये जलोढ़ हुआ है।



साक्षरता :- मानवीय संसाधनों के गुणात्मक पहलू को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा का अद्वितीय योगदान है।

इसलिए शिक्षा सामाजिक-आर्थिक विकास का एक अनिवार्य अंग बन चुकी है। आधुनिकीकरण एवं सामाजिक जागरुकता के स्तर को साक्षरता प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। किसी क्षेत्र के सम्पूर्ण सामाजिक व्यक्तित्व के ज्ञान के लिए साक्षरता का अध्ययन आवश्यक है (चान्दना 1980)। वस्तुतः शिक्षा, समाज की एक दिशा प्रदान करने एवं उनके प्रत्येक पहलुओं जैसे- सामाजिक कुरीतियों, भाषा संकीर्णता एवं जाति प्रथा आदि को परिमार्जित करने में सहायक सिद्ध होती है। इसलिए संसाधनों के नवीकरण एवं प्राविधिक परिवर्तनों की दिशा में इसकी उपयोगिता विवाद रहित है क्योंकि विकास की आत्मा के रूप में यह समाज का मूल आधार एवं वास्तविक मापदण्ड है।

सारणी 1 विकासखण्ड सरसावां में साक्षरता दर की तुलना (प्रतिशत में)

वर्ष	विकासखण्ड सरसावां	जनपद सहारनपुर	उत्तर प्रदेश	भारत
1991	33.38	35.96	40.71	52.21
2001	53.73	61.22	57.36	64.84
2011	67.24	70.55	69.7	73.0

स्रोत: प्राथमिक जनगणनासार 1991-2011

विकासखण्ड सरसावां में साक्षरता दर वर्ष 1991 में 33.38 प्रतिशत थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 53.73 प्रतिशत और 2011 में 67.24 प्रतिशत हो गयी जबकि जबकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता की दर वर्ष 1991 में 40.71 प्रतिशत थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 57.36 प्रतिशत और 2011 में 69.7 प्रतिशत हो गयी। यह विकासखण्ड सरसावां की साक्षरता दर से तीनों दशकों में अधिक थी। भारत की साक्षरता दर वर्ष 1991 में 52.21 प्रतिशत थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 64.84 प्रतिशत तथा 2011 में 73.0 प्रतिशत हो गयी जो तीनों दशकों में विकासखण्ड सरसावां की साक्षरता दर से तीनों स्तरों में अधिक हैं।

शैक्षणिक सुविधाएँ :- यह निर्विवाद सत्य है कि मानवीय संसाधनों के गुणात्मक पहलू को सुदृढ़ बनाने में शिक्षा की विशिष्ट भूमिका होती है। शिक्षा स्वयं ऐसा महत्वपूर्ण माध्यम है जो मानव समाज के विविध पक्षों जैसे – सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी क्षेत्रों में भिन्नात्मक परिवर्तन से परिचित कराता है (पाण्डेय, 1988, सिंह, 1986)। शिक्षा के माध्यम से कोई भी क्षेत्र अपने सामाजिक-आर्थिक स्वरूपों में परिवर्तन की प्रक्रिया को स्वीकार करता है, जो क्षेत्र के जनसामान्य या मानव संसाधन के आधारभूत आवश्यक विकास प्रक्रियाओं से अन्तर्सम्बन्धित होता है (क्रो. एवं क्रो.

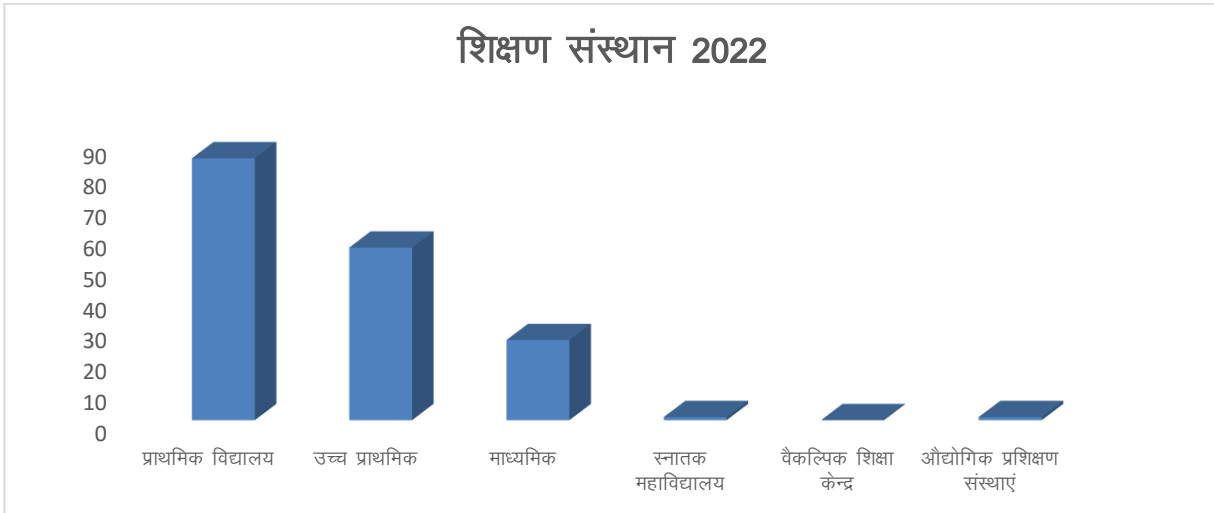
1955)। ग्रामीण विकास के परिप्रेक्ष्य में मानवीय क्षमता एवं वृद्धि हेतु शिक्षा प्रदायी शैक्षिक सुविधाएँ (संस्थाएँ) एक आवश्यक आधारित संरचना की भूमिका निभाती है। ये संस्थाएँ अध्ययन क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार के शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से मानवीय गुणवत्ता में अभिवृद्धि करके सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु आधार प्रस्तुत करती है। अतः प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र विकासखण्ड सरसावां में स्थित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का वितरण एवं जनसंख्या अनुपात के माध्यम से ग्रामीण विकास का मूल्यांकन किया गया है।

वर्तमान समय में अध्ययन क्षेत्र में कुल 169 शिक्षण संस्थाएँ हैं जो 2002 में 123 थीं। 2002 में प्राथमिक विद्यालय 111 तथा 2022 में 85 हो गये जिसका कारण उच्च प्राथमिक विद्यालय में उनका परिवर्तन है। उच्च प्राथमिक विद्यालय जो 2002 में 5 थे, तथा 2022 में बढ़कर 56 हो गये हैं। सन् 2002 में माध्यमिक विद्यालय की संख्या कुल 6 थी। सन् 2022 में बढ़कर 26 हो गयी है। इसी प्रकार महाविद्यालय 0 से बदलकर 1 हो गये हैं। अध्ययन क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 01 है। स्नाकोत्तर महाविद्यालय एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र नहीं हैं।

सारणी 2.: विकासखण्ड सरसावां : शिक्षण संस्थान (2002–2022)

शिक्षण संस्थान	2001–02	2021–22
प्राथमिक विद्यालय	111	85
उच्च प्राथमिक	5	56
माध्यमिक	6	26
स्नातक महाविद्यालय	0	1
वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र	0	0
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	1	1
योग	123	169

स्रोत: सांख्यिकीय प्रतिका 2002, 2022



इस विकास विकासखण्ड में शिक्षा मानव विकास का निर्धारण करता है, तथा उससे सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति निर्धारित होती है। शिक्षा का स्तर, व्यवसाय एवं आय तीनों एक साथ मिलकर समाज की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं इसलिए क्षेत्रीय विकास तथा सामाजिक प्रस्थिति को ऊँचा करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं का उचित वितरण अपेक्षित है। अध्ययन क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं की संख्या में वर्ष 2001 के बाद तीव्र वृद्धि हुई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विकासखण्ड में शिक्षा दिनोंदिन शिक्षण संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होने से बढ़ रही है।

विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर शिक्षको एवं छात्रों की स्थिति :- बालिकाओं की संख्या में कमी का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का झुकाव कम होना है तथा बालिका विद्यालयों की कमी भी इसका एक प्रमुख कारण है।

अध्ययन क्षेत्र में कुल शिक्षक की संख्या 748 (2022) थी जिनमें 312 पुरुष एवं 436 महिला थी। प्राथमिक विद्यालयों में कुल विद्यार्थियों की संख्या 13867 थी जिनमें 7787 बालक एवं 6080 बालिकाएं थी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुल विद्यार्थियों की संख्या 7352 थी जिसमें 4195 बालक एवं 3157 बालिकाएं थी। इण्टर कालेजों में कुल विद्यार्थियों की संख्या 6929 थी। जिनमें 1798 बालक एवं 5131 बालिकाएं थी। इसी प्रकार स्नातक स्तर पर कुल 37 विद्यार्थी थे जिनमें 2 बालिकाएं थी। आधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में कुल विद्यार्थियों की संख्या 253 थी। जिनमें 177 बालक एवं 76 बालिकाएं थी।

सारणी 3 विकासखण्ड सरसावां : विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या 2022

शिक्षण संस्थान	पुरुष	स्त्रियाँ	कुल
प्रा० विद्यालय	121	238	359
उ० प्रा० विद्यालय	126	162	288
मा० विद्यालय	52	33	85
स्नातक/स्नाकोत्तर महाविद्यालय	4	2	6
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	9	1	10
योग	312	436	748

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका 2022

इसी प्रकार बालिकाओं की अपेक्षा बालकों की संख्या ज्यादा है। इससे स्पष्ट है कि बालिकाएँ बालकों की अपेक्षा कम संख्या में शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं, इसका मुख्य कारण, रूढ़िवादी परम्परा, बालिका विद्यालयों की कमी एवं बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिभावकों का जागरूक न होना है।

दूरी के आधार पर शिक्षण संस्थाएँ :- सारणी 4 के विश्लेषण से यह विदित होता है कि सम्पूर्ण आबाद ग्रामों में से 102 ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध है जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय बालक 21 तथा बालिका विद्यालय 11 ग्रामों में अवस्थित है; एवं माध्यमिक विद्यालय बालक 9 ग्रामों में तथा मात्र दो ग्रामों में बालिका विद्यालय अवस्थित है।

सारणी 4 : विकासखण्ड सरसावां : दूरी के आधार पर शिक्षण संस्थाएँ 2022

विद्यालय	ग्रामों में	1 किमी० से कम	1-3 किमी०	3-5 किमी०	5 किमी० से अधिक	कुल
प्राथमिक	102	4	45	2	0	153
उच्च प्राथमिक बालक	21	3	87	29	13	153
उच्च प्राथमिक बालिका	11	1	36	21	84	153
मा० विद्यालय बालक	9	2	48	31	64	153
मा० विद्यालय बालिका	2	1	22	19	109	153

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका 2022

निष्कर्ष :- इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में प्राथमिक एवं सीनियर स्कूलों एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों को छोड़कर महाविद्यालय एवं स्नाकोत्तर महाविद्यालयों का अभाव है। यही कारण है कि अधिकांश लोग उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। निरक्षरता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान एवं अन्य कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य निरक्षरता समाप्त

करना है। परन्तु समुचित व्यवस्था एवं गुणवत्ता में कमी के कारण शिक्षा के क्षेत्र में यह विकासखण्ड पिछड़ा हुआ है।

सन्दर्भ :-

1. प्राथमिक जनगणनासार 1991-2011।
2. सांख्यिकीय पत्रिका 2002 एवं 2022।
3. क्रो, एल.एफ., एण्ड क्रो ए. (1955): इन इन्ट्रोडक्शन टू एजुकेशन प्रिन्टेड, इन यू.एस.ए. टोरन्टो इत्यादि।
4. चान्दना, आर.सी. (1987): "जनसुख्या भूगोल", कल्याणी पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
5. चौधरी, सी.एम. (1988): "ग्रामीण विकास में विकास और टेक्नालाजी का प्रभाव कुरुक्षेत्र" वर्ग - 32, अंक - 12।
6. तिवारी, आर.सी. (1958): अधिवास भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद।
7. राय, पी. एण्ड पाटिल, बी.आर. (1977), मैनुअल फार ब्लॉक लेबल प्लानिंग, मैकमिलन कम्पनी, दिल्ली।